कोविड बीमा के नवीकरण को नियामक की मंजूरी

सुब्रत पांडा
मुंबई, 13 अक्टूबर

- कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीमा नियामक ने कोविड से जुड़ी पॉलिसियों के नवीकरण, माइग्रेशन और पोर्टेबिलिटी की अनुमति दी
- योजना के तहत बीमा कराने वाले साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने के लिए अपनी सुविधा मुताबिक बढ़वा सकेंगे पॉलिसी की अवधि
- पॉलिसी की अवधि बढ़वाने पर 15 दिन की प्रतीक्षा अवधि नहीं रहेगी

कोविड-19 के मामले बढ़ने और वायरस के खत्म होने की संभावना न होने की स्थिति को देखते हुए बीमा नियामक ने कोरोना केंद्रित बीमा के दिशानिर्देशों में बदलाव किया है। अब इसके नवीकरण, माइग्रेशन और पोर्टेबिलिटी की अनुमति मिल गई है।

शुरुआत में बीमा नियामक ने कहा था कि इस तरह के उत्पादों पर आजीवन नवीकरण, माइग्रेशन और पोर्टेबिलिटी के नियम लागू नहीं होंगे। बहरहाल अब दिशानिर्देशों में बदलाव कर दिया गया है और 'कोरोना कवच' और 'कोरोना रक्षक' पॉलिसियों को पॉलिसीधारक की पसंद के मुताबिक साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने तक की किसी भी अवधि तक नवीकरण की अनुमति मिल गई है। साथ ही बीमा पॉलिसी की अवधि पूरी होने के पहले भी नवीकरण हो सकेगा।

इसके नवीकरण में 15 दिन की प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी और पॉलिसी कवरेज बाधारहित जारी रहेगी। नवीकरण के दौरान बीमित राशि में भी बदलाव किया जा सकेगा। नियामक ने कहा है कि अगर बीमित राशि बढ़ाई जाती है तो प्रतीक्षा अवधि सिर्फ बढ़ी राशि पर लागू होगी। जहां तक माइग्रेशन का मसला है, कोरोना कवच पॉलिसी के लिए बीमाकर्ता को किसी अन्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की पेशकश करने की स्वतंत्रता होगी। इसके अलावा ग्रुप पॉलिसी के मामलों में बीमाकर्ता बीमित सदस्यों को कोई अन्य व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा की पेशकश कर सकता है अगर सदस्य ग्रुप पॉलिसी से निकलता है।

हवाईअड्डों पर खुदरा बिक्री ने पकड़ी रफ्तार

अनीश फडणीस
मुंबई, 13 अक्टूबर

निजी हवाईअड्डों पर खुदरा बिक्री में धीरे धीरे सुधार नजर आ रहा है और आगामी दशहरा और दीपावली के त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या में इजाफा होने का अनुमान है। इसको देखते हुए उन्हें खरीदारी पर प्रोत्साहन देने की तैयारी की जा रही है। प्रोत्साहन में यात्री को आकर्षित करने की पहल, उपभोक्ता पेशकश और एफऐंडबी दुकानों पर क्यूरेटेड मेनू शामिल है।

बेंगलूरु इंटनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बायल) के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हवाई यात्रा आरंभ होने के बाद से विगत कुछ महीने से हवाईअड्डे पर आने वाले यात्रियों के साथ साथ उनके द्वारा किए जाने वाले खर्चों में हमें उत्साहजनक रुझान नजर आ रहा है।' नए आउटलेट के खुलने और हवाईअड्डे पर खरीदारी करने तथा भोजन करने के लिए यात्रियों को प्रोत्साहन दिए जाने से बिक्री में सुधार हुआ है। बेंगलूरु हवाईअड्डे पर हाल के हफ्तों में स्टारबक्स और औब्री ने दो नए खाद्य और पेय आउटलेट खोले हैं जबकि हेजन डेज पॉप-अप स्टोर के शीघ्र ही शुरू होने के आसार हैं।

बेंगलूरु हवाईअड्डा ने सभी प्रकार के यात्री खर्चों पर सितंबर के मध्य तक एक महीने का कर मुक्त अभियान भी चलाया था। हवाईअड्डे खुदरा दुकानों, शुल्क मुक्त, एफऐंडबी बिक्री, कार पार्किंग और विज्ञापन से होने वाली कमाई को गैर वैमानिक राजस्व की श्रेणी में रखते हैं। पिछले वित्त वर्ष में यह दिल्ली और बेंगलूरु हवाईअड्डों के कुल राजस्व का करीब 50 से 55 फीसदी रहा था।

कोल इंडिया की ई-नीलामी बढ़ी

श्रेया जय
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर

कोयले का आयात घटाने की कवायद कर रही है सरकार

- अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान पिछले साल की तुलना में ई-नीलामी 65 प्रतिशत बढ़ी है
- आयात घटाने की कवायद में कोल इंडिया ने की आयात करने वालों के लिए विशेष नीलामी
- विशेष नीलामी के माध्यम से गैर बिजली ग्राहकों ने की 124 लाख टन कोयले की खरीद
- पिछले साल कुल आयात में 40 प्रतिशत आयात ट्रेडर्स ने किया, जिसके मुताबिक बनी रणनीति

सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) में ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की बुकिंग में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान चार दौर की ई-नीलामी में सीआईएल ने 414 लाख टन कच्चे कोयले की बुकिंग की है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के दौरान 251 लाख टन बुकिंग हुई थी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि यह कोयले का आयात कम करने की कवायदों का हिस्सा है।

बिजली संयंत्रों व कुछ गैर बिजली कंपनियों के साथ दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति समझौते के माध्यम से कोयले की आपूर्ति के अलावा कोल इंडिया समय समय पर कुछ उद्योगों को ई-नीलामी से भी कोयला बेचती है।

जुलाई महीने में कोल इंडिया ने कोयले की विशेष श्रेणी की ई-नीलामी उन कंपनियों व कारोबारियों के लिए की थी, जो अपनी जरूरतों के लिए कोयले का आयात करते हैं। सीआईएल ने कहा कि इस विशेष नीलामी से 124 लाख टन की बुकिंग गैर बिजली ग्राहकों द्वारा की गई।

सीआईएल ने कहा, 'पिछले साल के कोयले के आयात के आंकड़ों से पता चलता है कि 40 प्रतिशत कोयले का आयात ट्रेडर्स ने किया। सीआईएल नीलामी से ज्यादा जोर देने का फैसला किया, जिसकी वजह से ज्यादा मात्रा में बिक्री हुई।'

सीआईएल के एक अधिकारी ने कहा, 'हमने अनुमान लगाया था कि कोविड के कारण नकदी का संकट होगा और आरक्षित मूल्य शून्य के करीब लाया गया था, जिससे कि हमारे ग्राहकों को मदद मिल सके और वे लॉकडाउन के दौरान ज्यादा कोयला उठा सकें।'

बिजली उत्पादकों के लिए विशेष अग्रिम नीलामी 100 लाख टन रही जबकि विशेष हाजिर नीलामी इस अवधि के दौरान 20 लाख टन रही। कंपनी अब गैर बिजली क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने की योजना बना रही है क्योंकि बिजली संयंत्रों को आपूर्ति की स्थिति अब सामान्य है।

छोटे उद्यमों के लिए समाधान केंद्र

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 13 अक्टूबर

लंबित भुगतान को लेकर परेशान उत्तर प्रदेश के छोटे व मझोले उद्यमियों के लिए अब हर मंडल में समाधान केंद्र खुलेगा। इसकी मदद से माल की आपूर्ति के बाद भुगतान पाने के लिए परेशान उद्यमियों की मदद होगी। अभी तक प्रदेश में इस तरह का अकेला केंद्र कानपुर में ही था।

प्रदेश सरकार ने अब सभी मंडल मुख्यालयों पर इसे खोलने का आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि एमएसएमई अधिनियम की धारा 15 के तहत खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच 45 दिनों में भुगतान करने का प्रावधान है। अधिनियम में तय समय में भुगतान न करने पर ब्याज दिए जाने की व्यवस्था है। इसके मुताबिक भुगतान में देर होने पर बैंक दर के मुकाबले तीन गुना तक ब्याज देय होता है। साथ ही भुगतान को लेकर किसी विवाद की दशा में मामले को फैसिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है जहां अधिकतम 90 दिन के भीतर निपटारे की व्यवस्था है।

प्रदेश सरकार के सभी मंडल मुख्यालयों पर समाधान केंद्र खोलने के कदम का स्वागत करते हुए एमएसएमई सेक्टर की प्रतिनिधि संस्था इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी व क्षेत्रफल के साथ ही 90 लाख छोटी व मझोली इकाइयों को देखते हुए केवल एक ही केंद्र नाकाफी था। आईआईए अध्यक्ष पंकज कुमार व महासचिव अश्विनी खंडेलवाल ने कहा कानपुर केंद्र पर उद्यमियों के ढेर सारे भुगतान विवाद लंबित हो गए थे और पूंजी फंस गई थी। आईआईए ने कई बार प्रदेश में एमएसएमई के भुगतान संबंधी वादों का मुद्दा उठाया था और कानपुर के बाहर के उद्यमियों को काफी परेशानी हो रही थी। पंकज कुमार ने कहा कि हर मंडल में केंद्र खोलने से एमएसएमई को सहूलियत मिलेगी।

मुंबई-कन्याकुमारी आर्थिक गलियारे पर चल रहा काम

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारत माला परियोजना के तहत मुंबई-कन्याकुमारी आर्थिक गलियारे के हिस्से के तौर पर 50,000 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को विकसित किया जा रहा है। गडकरी केरल के लिए 11,571 करोड़ रुपये की सात राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास अवसर पर ऑनलाइन तरीके से आयोजित समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कजाकोट्टम से मुक्कोला के बीच 27 किमी राजमार्ग परियोजना का भी उद्घाटन किया। *भाषा*

बीपीसीएल के निजीकरण की ओर सावधानी से बढ़ रहा भारत

रॉयटर्स
नई दिल्ली, 13 अक्टूबर

तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण की दिशा में भारत अपनी योजना पर 'बहुत सावधानी से चल' रहा है। इससे प्रक्रिया में और देरी के संकेत मिलते हैं।

सरकार ने बीपीसीएल में अपनी 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है, जिसकी पहली बार घोषणा नवंबर 2019 में हुई। यह सरकार की दर्जनों सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की योजना का हिस्सा है।

भारत ने मार्च 2021 तक इस वित्त वर्ष के अंत तक हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी। प्रधान ने वर्चुअल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में कहा, 'भारत पेट्रोलियम का विनिवेश प्राथमिकता में शामिल है।' उन्होंने कहा, 'लेकिन हम सभी नेटवर्थ बढ़ने व आकार पर विचारकर रहे हैं। सरकार विनिवेश के मामले में बहुत सावधानी से एक उचित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है।'

रॉयटर्स ने पिछले महीने खबर दी थी कि बीपीसीएल के निजीकरण की प्रक्रिया अप्रैल 2021 में शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष तक टल सकती है और संभव है कि सऊदी अरामको और रूस की रोसनेफ्ट इसमें हिस्सा न लें क्योंकि तेल के दाम कम होने के कारण उनकी निवेश योजना प्रभावित हुई है। पिछले साल नवंबर की तुलना में बीपीसीएल के शेयर 38 प्रतिशत गिरे हैं क्योंकि कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध के कारण भारत में ईंधन की मांग प्रभावित हुई है।

प्रधान ने कहा कि दीर्घावधि के हिसाब से देखें तो भारत में रिफाइंड उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और इसके लिए भारत की तेल शोधन क्षमता 40 प्रतिशत बढ़ाकर 2030 तक 23 करोड़ टन सालाना या 70 लाख बैरल प्रतिदिन करनी होगी।

सरकारी कंपनी, सऊदी अरामको और अबूधाबी नैशनल ऑयल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम बनाकर सरकार देश के पश्चिमी तट पर 12 लाख बीपीसीडी क्षमता की रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।

यह परियोजना अभी अटकी हुई है क्योंकि किसानों के विरोध के कारण संयुक्त उद्यम अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकेगा। प्रधान ने कहा कि स्थानीय मसलों की वजह से परियोजना प्रभावित हुई है, जिसका समाधान जल्द कर लिया जाएगा।

वित्त मंत्री के पैकेज से ई-कॉमर्स को फायदा

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 13 अक्टूबर

त्योहारों के पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उपभोक्ताओं के व्यय और पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन देने के कदमों की घोषणा की है। सरकार के मुताबिक इससे 1 लाख करोड़ रुपये की मांग का सृजन होगा, जिससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में मदद मिलेगी। उद्योग जगत से जुड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि इन कदमों का ई-कॉमर्स और ओमनीचैनल रिटेल कंपनियों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के डिजिटल ट्रांसफार्मेशन और भारत की अर्थव्यवस्था की बहाली में मदद मिलेगी।

इन कदमों में एलटीसी (यात्रा अवकाश भत्ता) कैश वाउचर और त्योहारी अग्रिम योजना शामिल है। इस योजना के तहत सरकारी व निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने एलटीसी पर कर मुक्ति का लाभ विभिन्न तरह की खरीद में ले सकेंगे। इसके अलावा 10,000 रुपये ब्याज रहित अग्रिम की सुविधा भी सरकारी कर्मचारियों को दी गई है।

- उद्योग जगत के अधिकारियों व विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के फैसले का ओमनीचैनल रिटेल व ई-कॉमर्स पर सकारात्मक असर
- सरकार के फैसले से ग्राहकों के हाथ पैसे आएंगे और ऑनलाइन खरीद को मिलेगा बढ़ावा

ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट के चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार ने कहा, 'वित्त मंत्री की घोषणाएं उपभोक्ता मांग बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है।' उन्होंने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर और त्योहारी अग्रिम योजना से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुमार ने कहा कि मांग बढ़ाने में ई-कॉमर्स की अग्रणी भूमिका होगी और सरकार के फैसले से ग्राहकों के हाथों में और पैसे आएंगे, जिन्हें वे ऑनलाइन खर्च कर सकेंगे, जिससे ऑनलाइन खरीद को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे लाखों एमएसएमई और विक्रेताओं को मदद मिलेगी।

ईवाई इंडिया में पार्टनर और ई-कॉमर्स और उपभोक्ता इंटरनेट के मार्केट लीडर अंकुर पाहवा ने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन कारोबार बहाल करने में अहम भूमिका निभाएगा, जिसमें चल रही महामारी के कारण गिरावट आई है। उन्होंने कहा, 'ग्राहकों की धारणा धीरे धीरे सुधर रही है। वित्त मंत्री द्वारा घोषित पहल से खपत बढ़ेगी, क्योंकि इसके माध्मय से लोगों के हाथ में नकदी दी गई है। इससे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों कारोबारियों को फायदा होगा।'

एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, 'सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा घोषणाएं लागू किए जाने के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के हाथ खर्च करने के लिए नकदी आएगी, जिसे वे अवधि बीतने के पहले खर्च करना चाहेंगे।'

भारत में ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है। रेडसीर के मुताबिक अनलॉक के बाद ई-कॉमर्स कारोबार कोविड के पहले के स्तर के 80 प्रतिशत पर पहुंच गया है। रिटेलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (आरएआई) के सीईओ कुमार राजगोपालन ने कहा, 'भारत का खुदरा उद्योग त्योहारी खरीद से उम्मीद बनाए हुए है, जिससे कि उसके घाटे की रिकवरी हो सके।' उन्होंने कहा कि खुदरा क्षेत्र ने वित्त मंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी।

कोविड के झटकों से उबर रहा फूड डिलिवरी कारोबार

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 13 अक्टूबर

जोमैटो का फूड डिलिवरी कारोबार कोविड-19 के पहले के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, वहीं स्विगी ने कहा है कि उसका कारोबार कोविड के पहले के ऑर्डर मूल्य की तुलना में 80 से 85 प्रतिशत पर पहुंच गया है। कई दौर के अनलॉक और रेस्टोरेंटों के खुलने के बाद कारोबार धीरे धीरे सुधर रहा है।

लॉकडाउन से अब तक स्विगी ऐप पर खाने, किराना, दवा व अन्य घरेलू सामान के लिए 10 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर किए गए हैं। करीब 200 से ज्यादा शहरों में कारोबार कोविड के पहले के जीएमवी (सकल कारोबारी मूल्य) की तुलना में 90 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जबकि 70 से ज्यादा शहरों में पूरी रिकवरी हो चुकी है।

स्विगी ने कहा, 'दरअसल पिछले 4-5 सप्ताह के दौरान दो अंकों की वृद्धि दर देखी गई है। खासकर जब लॉकडाउन खुला है और कोविड को लेकर डर कम हुआ है, तबसे ऑर्डर बढ़ रहे हैं।' कंपनी ने कहा, 'देश के कुछ छोटे इलाकों में तो ऑर्डर कोविड के पहले की तुलना में 200 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

जोमैटो के संस्थापक और सीईओ दीपेंदर गोयल ने कहा कि कई शहरों में कोविड के पहले के स्तर की तुलना में 120 प्रतिशत कारोबार हो रहा है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि फूड डिलिवरी का कारोबार निकट भविष्य में हर महीने 15-25 प्रतिशत बढ़ेगा।'

उन्होंने कहा कि मार्च के अंत से गुरुग्राम की जोमैटो ने कुल 9.2 करोड़ ऑर्डर की डिलिवरी दी है और फूड डिलिवरी या डिलिवरी एजेंट के कोविड के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सप्ताह पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा कि लोगों को खाने या इसके पैकेजिंग, प्रॉसेसिंग या डिलिवरी से डरने की जरूरत नहीं है।

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016 ("EXIT CIRCULAR") FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

Ess Vee Holdings Limited

(CIN: U74899DL1984PLC017393)
Registered Office: 42, Zamrudpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi-110048, India
Tel. No.: 011 - 43658031 | Email: admin@dexgroup.com

This Exit Offer Public Announcement **("Exit Offer PA")** is being issued by Mr. Virendra Kumar Singal, residing at B-120, Niti Bagh, New Delhi-110049, India **("Offering Promoter")**, one of the Promoters of Ess Vee Holdings Limited **("EVHL" or "the Company")**, on behalf of the Promoter Group of EVHL to provide exit opportunity to the Public Shareholders of EVHL in terms of the Exit Circular.

Ess Vee Holdings Limited was listed on Delhi Stock Exchange Limited **("DSE")**. Post the de-recognition of DSE by SEBI, EVHL was shifted to the Dissemination Board ("DB") of BSE Limited **("BSE")**.

SEBI, vide the Exit Circular, has stipulated the procedure for exit of Exclusively Listed Companies ("ELCs") from the DB. In terms of clause (i) of Annexure A of the Exit Circular, the Offering Promoter has appointed **Khambatta Securities Limited, a Category-I Merchant Banker registered with SEBI and empanelled as an Expert Valuer on the panel of BSE ("Independent Valuer")** for valuation of shares of EVHL and related services. The Independent Valuer, after taking into account the applicable valuation methodologies, has issued its valuation report dated October 12, 2020 and determined the fair value of One Equity Share of EVHL as ₹ 423.60 (Four Hundred Twenty-three Rupees and Sixty Paisa only).

In view of the above, the Offering Promoter has decided to offer exit to the Public Shareholders of EVHL at price of ₹ **423.60 (Four Hundred Twenty-three Rupees and Sixty Paisa only)** per Equity Share (equivalent to the fair value per Equity Share as determined by the Independent Valuer) **["Offer Price"]**.

Further, SEBI vide its letter MRD/OW/DSA//2017/17463/1 dated July 25, 2017 communicated to the BSE and NSE **["SEBI Letter"]**, inter-alia, permitted that, public shareholders/investors who are willing to remain as shareholders of the Company and do not want an exit may be allowed to do so and the Designated Stock Exchange **(in the present case BSE)** may obtain an undertaking from the investors who do not want an exit; consequentially the exit obligation of the Promoters will be reduced accordingly.

In terms of above mentioned SEBI Letter, Public Shareholders who are willing to remain as shareholders of EVHL and do not want an exit **shall send an undertaking to this effect ("in the format available at the registered office of the Company or can be requested from admin@dexgroup.com")** either by Registered Post/Speed Post/Courier, at their own risk or by hand delivery at the registered office of EVHL at 42, Zamrudpur Community Centre, Kailash Colony Extension, New Delhi-110048, India within 10 days of publication of this Exit Offer PA **i.e. on or before the closure of business hours on Saturday, October 24, 2020**.

Post the expiry of aforementioned 10 days period, the Offering Promoter will initiate the process of making an Exit Offer to those public shareholders who have not opted to continue as shareholders of EVHL **("Remaining Public Shareholders")**.

Offering Promoter undertakes that Offer Letter containing the relevant details relating to Exit Offer including dates of Opening and Closing of Exit Offer, Offer Price, documents required to be submitted for participating in Exit Offer shall be sent to Remaining Public Shareholders for participating in the Exit Offer.

In accordance with the Exit Circular read with the Circulars/Notices issued by BSE, Offering Promoter will open an Escrow Account with scheduled commercial bank and deposit an amount equivalent to/more than the 100 % of the Total Consideration (Offer Price* Remaining Public Shares) payable under the Exit Offer at least one day before the dispatch of Exit Offer Letter.

Shareholding Details: As on the date of this Exit Offer PA, the paid up share capital of EVHL is ₹ 24,80,000 consisting of 2,48,000 Equity Shares of ₹ 10 each. Out of these, Promoter Group holds 2,38,000 Equity Shares representing 95.97% of the Paid up Equity Share Capital and balance 10,000 Equity Shares representing 4.03% of the Paid up Equity Share Capital are held by the Public Shareholders.

This Exit Offer PA is expected to be available at the website of BSE at www.bseindia.com and at the website of Independent Valuer at www.khambattasecurities.com.

For and on behalf of promoters of
Ess Vee Holdings Limited,
Sd/-
(Virendra Kumar Singal)
Offering Promoter

Place: Delhi
Date: October 13, 2020

Raka

बीएस सूडोकू 3868

2		5						
6				8		2	9	
			5		9			
	4		2		1		8	
9						1		
					7	3		
		4			8	7	3	
			6					
			7			5	1	8

परिणाम संख्या 3867

2	1	6	5	4	7	9	3	8
7	8	4	6	9	3	2	5	1
5	3	9	8	1	2	7	4	6
6	2	5	9	7	8	3	1	4
3	7	1	4	2	5	6	8	9
9	4	8	3	6	1	5	7	2
4	6	3	7	8	9	1	2	5
8	5	2	1	3	6	4	9	7
1	9	7	2	5	4	8	6	3

कैसे खेलें? हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान ★★☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | पंजाब

बंद भाव रुपये प्रति क्विंटल

लखनऊ
गेहूं दड़ा 1620/1630, गेहूं शरबती 2500/2650, चावल शरबती सेला 3500/3550, स्टीम 3900/4000, लालमती 2600/2700, चावल (सोना) 2300/2400, दाल अरहर सवा नं. 9000/9200, पटका 10800/11000, रिजैक्शन 7200/7500, चना दाल 6600/6800, चना देशी छना 6600/6700, चना चापा छना 6700/6800, मटर विदेशी 7800/8000, उड़द साबुत (काला)9200/10700, दाल उड़द (काली) 9400/11700, उड़द धोया 10500/12200, मसूर छोटी 7000/7400, मलका 6600/6700, किराना: जीरा 14600/18000, लालमिर्च गुंटूर 15500/19000, हल्दी निजाम गट्ठा (50 किलो) 3600/4300, धनिया एमपी 7400/10500, छोटी इलायची (किलो) 1600/2000, बड़ी इलायची 450/560, कालीमिर्च (किलो) 380/425, सुपारी (किलो) 390/445, सौंफ मोटी 7800/10400, मंगरैल 22000/23000, चिरौंजी (किलो) 1050/1100, मखाना 460/620

कानपुर
गेहूं लूज 1620/1630, जौ 1300/1320, चावल मसूरी 1900/2100, चावल मोटा 2000/2050, देशी चना 6000/6100, चना छना 6200/6400, दाल चना 6600/6800, विदेशी मटर 7500/8000, पिचकी 5800/6000, मटर दाल 7500/8000,अरहर लेमन 7200/7250, दाल अरहर 9000/10000, स्पेशल 9000/9500,उड़द एसक्यू 9600/9700, एफएक्यू 8200/8300, राजमा चित्रा 10300/10800, मूंग 6000/7300, मसूर छोटी 6100/6400, छांटी 7000/7500, सरसों 5000/5100, तिल सफेद 8300/8400, सोया (टीन) 1850/1880, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन) 2200/2300, सरसों खल 2450/2500, पामोलिन 1850/1900, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1700/1740, मधुसूदन देशी घी 5600, वासुदेव 5150, अलसी 6300/6500, धनिया: लोकल 7800/8000, राजस्थान 8300/8500, बढ़िया 9800/10500, हल्दी 7200/8300, जीरा 14800/18200, अजवायन 16000/21000, मेथी 7100/7300, मखाना 450/625, कालीमिर्च (किलो) 360/400, लालमिर्च (किलो) तेजा 175/195, (334) न. 150/160, सुपारी (किलो) केरल 400/440, कर्नाटक चिकनी 430/450, गोला 18000/20000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1112, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1140, फ्लैक 1102, डीएमओ 855, टरपीन लैस बोल्ड 1145

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू नया 1140/1200, खुरपा 1025/1075,चाकू 1200/1350, रसकट 1155/1160, शक्कर 1200/1250, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3290, सिहोरा 3210, थाना भवन 3215, बुढ़ाना 3225, चीनी हाजिर 3450/3500

हापुड़
अनाज-दाल: गेहूं 1690/1700, चावल परमल 2100/2200, डुप्लीकेट बासमती सेला 3700/3800, बासमती 1121 स्टीम 6000/6100, चना 5600/5700, चनादाल 6700/6800, काबली चना 6800/7700, राजमा देशी चित्रा 9800/10200, मटर दाल 6600/6700, दाल अरहर 10000/11000, मसूर 6500/7000, उड़द देसी 7900/8100, दाल उड़द 9500/10500, धोया 10000/11000, मूंग यूपी 6900/7000, मूंग दाल 8500/9500, गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3450/3500, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1000/1025,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)120, राइसब्रान (अखाद्य) 118, खल सरसों 2300, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 850, लाल 850, कंटीन्यूअस 850, सरसों (टन) 19000, अनाज: गेहूं 1780/1785, आटा (50 किलो)1000, मैदा 1140, चोकर (49 किग्रा) 820,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 9500/10200, अरहर दाल 9500/10800, उड़द साबुत 9300/9500, उड़द धोया 10000/11000, छिलका 9800/10300, दाल मसूर 7500/8500, चनादाल 6400/6700, एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 2550, काबली चना 6000/7800, मूंग साबुत 6700/7000, मूंग धोया 7500/8500, चावल: डीबी 4600/4700, शरबती स्टीम 4050/4150,चावल 1121 सेला 5000/5100, *एनएनएस*